Newspaper Clips

July 4, 2015

Millenium Post ND 04/07/2015 P-13

PowerGrid Director (Personnel) Ravi P Singh and FITT-IIT (Delhi) Managing Director Dr Anil Wali signed an MoU in the presence of IIT (Delhi) Director Prof K Gupta for long-term collaboration in technical training and certification for PowerGrid executives

Dainik Jagran ND
04/07/2015 P-11

दिल्ली के एनबीसीसी सेंटर में खुलेगा आइएसएम

जासं, धनबाद : आइआइटी दिल्ली से मुकाबले की रणनीति के तहत आइएसएम ने दिल्ली के ओखला फेज वन स्थित एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन)में एक्सटेंशन सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उसने शुक्रवार को पहली किस्त चार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इस एक्सटेंशन सेंटर में एक साथ कई कोर्स शुरू किए जाएंगे। आइआइटी दिल्ली को देखते हुए विदेशी विवि के शॉट टर्म कोर्स शुरू करने पर भी मंथन किया जा रहा है। एनबीसीसी सेंटर के 26 हजार वर्गफुट में एक्सटेंशन सेंटर खोला जाना है। इसकी लागत 40 करोड़ रुपये है। दिल्ली में एक्सटेंशन सेंटर खुलने का सबसे अधिक फायदा छात्रों को ही होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनियां कैंपस के लिए धनबाद नहीं आती थीं उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। इसके अलावा संस्थान में विदेशी छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी।

Amar Ujala ND 04/07/2015 P-11

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शीर्ष अफसरों की दूरी पर फिर मचा हल्ला

अमर उजाला ब्यूरो

स्मृति ईरानी की निजी सचिव बिनिता ठाकुर के अचानक हटने पर भी विवाद

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शीर्ष अफसरों के तबादले लेने की खबरों पर हल्ला मच गया है। कई शीर्ष अधिकारियों के मंत्रालय से पीछा छुड़ाकर दूसरे विभागों में पोस्टिंग कराने की बात एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला स्मृति ईरानी की निजी सचिव बिनिता ठाकुर के अचानक हटने का है। बताया जा रहा है कि 1996 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी बिनिता ने तबादले के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन मंजूर हो गया है। कांग्रेस ने भी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के कामकाज के अंदाज पर सवाल उठाया है।

पिछले एक साल से मंत्रालय और उससे जुड़े शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों और पदाधिकारियों के तबादलों, हटने और हटाने का खेल जारी है। दिलचस्प यह है कि अधिकारियों के हटने को लेकर मंत्रालय के गलियारों में अजीबोगरीब कारण सुनने को मिलते हैं। मार्च, 2015 में मंत्रालय की संयुक्त सचिव राधा एस चौहान के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में तबादला लेने पर भी चर्चा बड़ी गरम रही थी। उस समय चर्चा थी कि यूपी कैडर की आईएएस अफसर का कमरा छीनकर शास्त्री भवन में एक छोटा कमरा दिया जा रहा था। इससे वह नाराज थीं। उनके ईरानी से तालमेल नहीं बैठने की बात मंत्रालय के गलियारों में सुनी जा सकती है। बिनिता ठाकुर का भी कमरा कुछ समय पहले बदला गया था। कहा जा रहा है कि वह भी इस बात से नाराज थी। पिछले एक साल में मंत्रालय में रहे तीन और आईएएस अधिकारी दूसरे विभागों में तबादला ले चुके हैं। अगस्त 2014 में संयुक्त सचिव वीणा ईश अपने मूल कैडर आंध्र प्रदेश में वापस चली गईं। जून 2014 में संयुक्त सचिव जगमोहन सिंह राजू भी अपने कैडर तमिलनाडु में लौट गए।

अप्रैल 2015 में संयुक्त सचिव प्रवीण प्रकाश का ग्रामीण विकास में तबादला हो गया। वहीं कई अधिकारियों को भी इधर-उधर भेजने की खबर चर्चा का विषय रही। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी नागेश कुमार को उनके कैडर में भेज दिया गया। उधर, मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमरजीत सिन्हा को सांख्यिकी संकाय में भेजना सबसे ज्यादा विवादों में रहा है।

सिन्हा तकनीकी शिक्षा का काम देख रहे थे। चर्चा है कि तीन आईआईटी भुवनेश्वर, रोपड़ और पटना के निदेशक पद पर ईरानी अपने पसंद के लोगों को बैठाना चाहती थी। मगर निदेशक को लेकर अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में गठित सर्च पैनल कमेटी ने दूसरे नामों को चुन लिया था। कहा जाता है कि ईरानी की ओर से उनके पसंद के लोगों को चयन सूची में रखने के लिए कहा गया था। मगर सिन्हा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग में भेज दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा कहते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय लगातार विवादों में है। इससे शिक्षा के क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए।

School board hurdle to IIT, NIT hopefuls

Basant Kumar Mohanty

http://www.telegraphindia.com/1150704/jsp/nation/story_29517.jsp#.VZd-klK2Iy0

New Delhi, July 3: About 8,000 students seeking seats at the Indian Institutes of Technology and the National Institutes of Technology are in danger of losing the opportunity because of their school boards' tardiness.

These candidates, who include 100 from Bengal, are yet to get their ranks in the JEE Main, conducted by the Central Board of Secondary Education, because their school boards haven't sent their Class XII scores to the CBSE.

The all-India ranks of the remaining 13 lakh candidates were announced on June 30, and registration for common counselling for IIT and NIT seats began on July 1.

"Unless I get my JEE Main rank, I can't participate in counselling. I'm worried whether I'll get my rank in time," a student from Hyderabad said, echoing the fears of thousands, including 1,200 from Telangana alone.

The all-India rank is generated by giving 60 per cent weightage to a candidate's JEE Main score and 40 per cent to his Class XII board marks after normalising the scores across boards. School boards, therefore, need to provide the scores of all their Class XII science students to the CBSE.

But in an unprecedented lapse, some 20-odd boards sent incomplete data this year, leaving out the scores of hundreds of students. So, the CBSE had to omit from its rankings, at least for now, those among these students who took the JEE Main.

CBSE chairperson Satbir Bedi told **The Telegraph** that her board had written to each of these 20-odd school boards "several times between June 20 and 25" and some had rectified their lapse. But 12 boards, including Bengal's, are yet to do so.

Bedi said the ranks of the excluded students could be published in two to three days after their school boards send the data. Such additions will, however, necessitate modifications to the announced ranks.

Once the first round of counselling ends, the students still denied rankings would lose their chance.

NIT seats are filled solely on the basis of JEE Main rankings. These rankings, however, play no role in IIT admissions, although the school boards' lapse will hurt IIT hopefuls too.

IIT seats are awarded on the basis of candidates' scores in the JEE Advanced, conducted by the IITs themselves after the JEE Main, and an interview. However, students need to have scored at least 75 per cent in their board exams to be eligible - and this cannot be determined if their board scores haven't reached the IITs via the CBSE.

A candidate's JEE Main scores - as opposed to his JEE Main rankings which give weightage to board scores too - decides his eligibility to take the JEE Advanced, which was held recently after the JEE Main scores were announced about a month ago.

Among the defaulting boards are those from Chhattisgarh, Bihar and Goa as well as the CISCE, which conducts the ISC exam.

Telangana principal secretary Ranjiv R. Acharya has written to the Union human resource development

ministry claiming that all the data had been provided to the CBSE.

For the first time, the IITs and the NITs are holding common counselling, which means a candidate can get an offer from only one set of institutes and cannot block seats in both